

तारीख हुक्म	राजस्व अपील संख्या 29/2018 सुरतीदेवी बनाम बादरा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	--	--

19/12/2022

अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अन्तरिम आदेश दिनांक 24.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। हस्तगत प्रकरण मे हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2018 से निरन्तर अंतिम आदेशिका तक अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम आदेश दिनांक 24.01.2013 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2013 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है। प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन/लंबित मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियो मे न्यायहित को मद्देजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाकर प्रकरण को लंबा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के इस मत पर अपनी सहमति जाहिर की गई।

प्रकरण मे अपीलांट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मे वर्णित तथ्यो पर बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 05 से 20 के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा एवं साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से 04 दिनांक 24.01.2013 को जो नोटिस भरकर प्रस्तुत किये गये, उक्त नोटिस विधिवत भरकर प्रस्तुत नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण के सम्मन विधिवत तामिल नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का विधिवत अवसर दिये बिना जैर अपील

8 राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 29/2018</p> <p style="text-align: center;">सुरतीदेवी बनाम बादरा</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	---	--

आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

अपीलांत अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा अपीलांत एवं रेस्पोजेन्ट संख्या 05 से 20 के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा एवं साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है।

हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील अन्तरिम व्यादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने के सम्बन्ध में जो प्रावधान दिए गए हैं, उनमें मुख्य रूप से आदेश 39 नियम 1 से 4 मुख्य हैं, जहां तक आदेश 39 नियम 3 सीपीसी का प्रश्न है, इस संबंध में आदेश 39 नियम 3 सी पी सी का उद्धरण इस प्रकार है—

आदेश 39 नियम 3

3. *Before granting injunction, Court to direct notice to opposite party-*

*The Court shall in all cases except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction direct notice of the application*

*for the same to given to be the opposite party*

*Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by delay, and require the applicant-*

१  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 29/2018</p> <p style="text-align: center;">सुरतीदेवी बनाम बादरा</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	---	--

(A) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with-

1. a copy of the affidavit filed in support of the application.
2. a copy of the plaint and
3. copies of documents on which the applicant relies, and

(b) to file, on the day on which such in such injunction is granted or on the day immediately following that day, and affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered sent.

आदेश 39 नियम 3(क) सी.पी.सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहाँ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय द्वारा 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणों को अभिलेखित करना चाहिए।


उपरोक्त कानून के सन्दर्भ में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील व्यादेश एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश है। विधि अनुसार जहां एकपक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, ऐसे मामले को न्यायालय द्वारा 30 दिवस के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणों को अभिलेखित करना चाहिए। हस्तगत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की फोटोप्रति आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत दिनांक 24.01.2013 से 05.04.2018 तक तलबी भी पूर्ण नहीं हुई। सिविल

राजस्व अपील प्राधिकारी  
पाली

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">राजस्व अपील संख्या 29/2018</p> <p style="text-align: center;">सुरतीदेवी बनाम बादरा</p> <p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p style="text-align: center;">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
-------------	---	--

प्रक्रिया संहिता के प्रावधानुसार एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का 30 दिवस में निस्तारण किये जाने का विधिसम्मत कारण भी पत्रावली की आदेशिकाओ में अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र का लगभग 09 वर्षों से अंतिम निस्तारण नहीं किये जाने से हितबद्ध पक्षकारो को कई प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड रहा है एवं प्रार्थना पत्र लंबित होने से पक्षकारो को न्याय प्राप्त होने मे अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। जो कि न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। प्रकरण मे किसी भी पक्ष की ओर से हाजा न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के संबध माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित किसी भी आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। उपखंड अधिकारी चितलवाना द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 268/2014 बउनवान कोजा के कायम मुकाम बादरा वगैरा बनाम भेरा गोद धन्ना वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 24.01.2013 को यथावत रखा जाता है। चूंकि प्रकरण में निहित कानूनी बिन्दुओ की पालना करवाई जानी आवश्यक है, तदनुसार उपखंड अधिकारी चितलवाना को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन राजस्व प्रकरण संख्या 268/2014 बउनवान कोजा के कायम मुकाम बादरा वगैरा बनाम भेरा गोद धन्ना वगैरा के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानो की पालना करते हुए उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 30 दिवस के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 पाली